

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : ०7 नवम्बर, 2007

विषय:- न्यायालय भवन, डीडीडहाट, जिला पिथौरागढ़ हेतु फर्नीचर का क्रय किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4204/यू०एच०सी०/एडमिन-बी./निर्माण(पी/डी)/2007, दिनांक 27.09.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवनिर्मित न्यायालय भवन, डीडीडहाट, जिला पिथौरागढ़ के फर्नीचर हेतु रु० 4,08,000/- की लागत के आगणन का टी०ए०सी० से परीक्षणोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 4,08,000/- (चार लाख आठ हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (4) कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करले कि पर्चेज नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय एवं । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।
- (5) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-1035/XXVII(5)/2007, दिनांक 05.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 26-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-11-दो(2)/07-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़ ।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ ।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।